दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 37 | मूल्य 05 रुपये | 01-07 फरवरी, 2026

देवभूमि में यूसीसी से सामाजिक न्याय का नया अध्याय

समाज में समानता को कमजोर करने की कोशिश

HERITAGE AVIATION
onward on wings

पहाड़ों की दूरियां हो रही हैं कम,
हेरिटेज एविएशन की सस्ती उड़ानों के संग

UDAN
Ude Desh ka Aam Nagrik

Book now
www.airheritage.in
✆ 88510-72020

देहरादून एयरपोर्ट से

देहरादून से नैनीताल नैनीताल से देहरादून	8:00 & 11:30 8:50 & 12:20	मात्र ₹ 3500
देहरादून से बागेश्वर बागेश्वर से देहरादून	11:15 & 15:05 10:20 & 15:30	मात्र ₹ 3500
देहरादून से न्यू टिहरी न्यू टिहरी से देहरादून	9:55 & 13:30 11:00 & 14:35	मात्र ₹ 2000
न्यू टिहरी से श्रीनगर श्रीनगर से न्यू टिहरी	10:10 & 13:45 10:50 & 14:25	मात्र ₹ 1000
श्रीनगर से गौचर गौचर से श्रीनगर	10:20 & 13:55 10:35 & 14:10	मात्र ₹ 1000

हल्द्वानी हेलीपोर्ट से

हल्द्वानी से मुनस्यारी मुनस्यारी से हल्द्वानी	7:45 & 12:35 8:20 & 13:10	मात्र ₹ 5000
हल्द्वानी से पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ से हल्द्वानी	9:40 & 12:30 10:35 & 13:25	मात्र ₹ 4000
हल्द्वानी से चंपावत चंपावत से हल्द्वानी	9:00& 15:25 9:15 & 15:45	मात्र ₹ 2000
हल्द्वानी से बागेश्वर बागेश्वर से हल्द्वानी	9:55 & 14:00 11:55 & 14:25	मात्र ₹ 3500
हल्द्वानी से अल्मोड़ा अल्मोड़ा से हल्द्वानी	11:15 & 14:10 12:00 & 14:55	मात्र ₹ 3500

पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से

पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा अल्मोड़ा से पिथौरागढ़	11:45 & 14:40 11:30 & 14:25	मात्र ₹ 1500
पिथौरागढ़ से मुनस्यारी मुनस्यारी से पिथौरागढ़	10:05 & 12:55 10:20 & 13:10	मात्र ₹ 2500

5% Gst extra

instagram.com/flywithheritage
facebook.com/heritageaviationpvtltd
twitter.com/flywithheritage

KRISHNA MEDICAL CENTER

KMC We Care

NABH ACCREDITED SUPER SPECIALITY HOSPITAL

State Of The Art Dialysis Unit At KMC

- Gastro & Endoscopy Unit
- Cardiology & Cath Lab
- Critical Care Unit
- Dialysis Center

ECHS | CGHS | ESI | Golden Card

For Queries :
+91 7088159000, 0135-2654321

Krishna Medical Center, 22- Inder road, Dalanwala, Dehradun | www.kmchospital.co.in

JAIRAM SINGH MEMORIAL SIKSHAN EVAM NARI UTTHAN

Vikas Nagar, Uttarakhand

जय राम सिंह मेमोरियल शिक्षण एवं नारी उत्थान समिति

चकराता, विकासनगर की ओर से

देवभूमि उत्तराखण्ड एवं चकराता प्रखण्ड के समस्त निवासियों को

77वें गणतंत्र दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं !!

हमारे आर्दश एवं प्रेरणास्रोत, मार्गदर्शक एवं समाज सेवा के लिए समर्पित
स्वः श्री जय राम सिंह तोमर जी की प्रेममयी स्मृति में स्थापित
जय राम सिंह मेमोरियल शिक्षण एवं नारी उत्थान समिति,
पहाड के दुर्गम क्षेत्रों विद्यालयी शिक्षा एवं नारी उत्थान व सशक्तिकरण
के लिये स्थापित एवं उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध है।

चेयरपर्सन, श्रीमती शीला जोशी सिंह
संस्थापक, डॉ रणबीर सिंह
सचिव, श्री जयपाल सिंह तोमर

सादर स्मृति में :

स्व: श्री जय राम सिंह तोमर जी

(15.08.1936 to 25.05.2000)

वर्ष 15 | अंक 37

दिव्य हिमगिरि

01-07 फरवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा आईशा प्रिंटिंग प्रेस, 292/1, चुक्खूवाला, ओंकार रोड, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

संपादकीय

विमान हादसों से सबक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की एक विमान हादसे में मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। इस त्रासदी ने न केवल देश के एक कुशल नेता को छीन लिया, बल्कि उन दर्दनाक हादसों की कड़वी यादें भी ताजा कर दीं, जिनमें पहले भी देश ने कई राजनीतिक दिग्गजों और प्रमुख हस्तियों को असमय खोया है। पुणे जिले के बारामती में हुए इस हादसे की अब कई कोणों से जांच की जा रही है, मगर सवाल है कि इससे पहले हुई ऐसी दुर्घटनाओं से क्या सरकारी तंत्र ने कोई सबक नहीं लिया? आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त हवाई अड्डे पर दृश्यता कम थी। अगर स्थिति वास्तव में जोखिमपूर्ण थी, तो विमान को उतरने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरा, यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में क्या ऐसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है? गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे जिला के बारामती में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीचे आने के बाद उसमें धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई। इससे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता संजय गांधी, वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया, वर्ष 2011 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, वर्ष 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वर्ष 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे दिग्गजों को भी देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब 'नहीं' था। इसके बाद विमान ने आसमान में ही एक चक्कर लगाया। इससे स्पष्ट है कि हवाई अड्डे पर परिस्थितियां विमान को उतारने के अनुकूल नहीं थीं। यह दावा भी किया जा रहा है कि दूसरी बार पूछे जाने पर पायलट ने सकारात्मक जवाब दिया। मगर सवाल है कि क्या किसी तरह के जोखिम की आशंका के बीच विमान को उतारने की अनुमति दी जा सकती है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन कैसे हुआ क्रैश? केंद्रीय मंत्रालय ने दी एक-एक पल की जानकारी अजित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उपमुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकल कर उन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी के नाम और चिह्न के साथ-साथ दल के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद वे राजग नीत महायुति में शामिल हो गए थे। उनके नेतृत्व वाली राकांपा ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनाव में शरद पवार की अगुआई वाली पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसके बाद सियासी गलियारों में अजित पवार और शरद पवार के बीच नजदीकियां बढ़ने की अटकलें भी जोर पकड़ रही थीं। ऐसे में विपक्षी दल इस हादसे की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विमान दुर्घटना की निष्पक्ष और गहन जांच हो, ताकि हादसे के असली कारण सामने आ सकें। सरकारी तंत्र को भी इस तरह के हादसों से सबक लेकर व्यवस्था में जरूरी सुधार करने चाहिए, ताकि भविष्य में और कोई विमान दुर्घटना न हो।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

अंकिता हत्याकांड की जांच को भटकाने का प्रयास कर रही उत्तराखंड की भाजपा सरकारः गणेश गोदियाल

गणेश गोदियाल ने कहा कि 'मुख्यमंत्री के ऐलान के 15 दिन बाद भी साफ नहीं कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई या नहीं, अंकिता के माता-पिता ने मामले में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने और सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी।'

कांग्रेस ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को भटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा के 15-17 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने वास्तव में सीबीआई को जांच सौंपने का औपचारिक प्रतिवेदन भेजा भी है या नहीं।

कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की राय लेकर इस मामले में दोबारा जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान अंकिता के माता-पिता ने लिखित रूप में दोषियों को फांसी दिए जाने, मामले में शामिल वीआईपी का नाम उजागर किए जाने और सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी।

गोदियाल ने कहा कि यह स्वाभाविक था कि मामले में पीड़ित पक्ष, यानी अंकिता के माता-पिता के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की जाती। लेकिन सरकार ने पीड़ित परिवार की बजाय एक तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच कराने की बात की, जिससे संदेह पैदा होता है कि जांच को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सीबीआई को भेजा गया प्रतिवेदन अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार नई एफआईआर के आधार पर इस मामले में वीआईपी के शामिल होने को एक काल्पनिक स्थिति बनाते हुए उसकी जांच करवाना चाहती है। जबकि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यथार्थ है कि एक वीआईपी को सर्विस देने से मना करने पर एक लड़की की जान ली गई है। जब कांग्रेस ने यह बात कही कि जांच इस यथार्थ की ही होनी चाहिए, तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिए और अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है या नहीं। सीबीआई की तरफ से भी इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है।

भाजपा सरकार पर प्रभावशाली लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपियों द्वारा स्वयं नार्को टेस्ट की मांग किए जाने के बावजूद सरकारी पक्ष ने अदालत में इसका विरोध किया, जो आपराधिक मामलों में दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रुख से ऐसा लगता है कि उसे डर था कि नार्को टेस्ट से सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं।

गोदियाल ने जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक किए जाने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस मामले में एसआईटी की पूर्व प्रमुख, जो अब सीबीआई में वरिष्ठ पद पर हैं, को इस जांच प्रक्रिया से दूर रखा जाए।

इसके अलावा गोदियाल ने उधम सिंह नगर में एक किसान की आत्महत्या का मामला उठाते हुए बताया कि मृतक ने पुलिस अधिकारियों के नाम लेकर उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बावजूद संबंधित एसएसपी को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मांग की कि उस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

महिला स्वास्थ्य और पोषण

डाइटिशियन वंदना,
फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट

स्वस्थ नारी, स्वस्थ समाज की आधारशिला महिला समाज की आधारशिला होती है। वह परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज–तीनों स्तरों पर अपनी भूमिका निभाती है। परंतु अक्सर यह देखा गया है कि अपने अनेक दायित्वों के बीच महिला अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाती। बदलती जीवनशैली, अनियमित खानपान, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता के कारण आज महिलाओं में अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में महिला स्वास्थ्य और पोषण पर गंभीरता से ध्यान देन

अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और सशक्त समाज की 0103 नींव रखती है। महिला जीवन के विभिन्न चरण और स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ महिला का शरीर जीवन के प्रत्येक चरण में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तनों से गुजरता है। इन परिवर्तनों के अनुरूप पोषण एवं देखभाल की आवश्यकता भी बदलती रहती है।

1. किशोरावस्था किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसी समय मासिक धर्म की शुरुआत भी होती है। आयरन की कमी से एनीमिया की संभावना कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से हडिड्यों का कमजोर होना जंक फूड और अनियमित भोजन से हार्मोनल असंतुलन इस अवस्था में संतुलित आहार न मिलने पर आगे चलकर कमजोरी, थकान और प्रजनन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2. युवावस्था एवं गर्भावस्था इस चरण में महिला घर और कार्य दोनों की जिम्मेदारियाँ निभाती है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक दुर्बलता आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी की आवश्यकता मानसिक तनाव और नींद की कमी गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण न केवल माँ के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि होने वाले शिशु के संपूर्ण विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है।

3. मध्यम आयु और रजोनिवृत्ति रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल बदलावों के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं: वजन बढ़ना हडिड्यों का कमजोर होना (ऑस्टियोपोरोसिस) हृदय रोगों का खतरा चिड़चिड़ापन और चिंता इस अवस्था में संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आवश्यक है। महिलाओं में बढ़ती सामान्य स्वास्थ्य समस्याएँ वर्तमान समय में महिलाओं में निम्नलिखित समस्याएँ सामान्य होती जा रही हैं: आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया थायरॉयड और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) मधुमेह और उच्च रक्तचाप मोटापा कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी इन समस्याओं के मुख्य कारण असंतुलित आहार, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक तनाव हैं। संतुलित आहार: महिला स्वास्थ्य की कुंजी संतुलित आहार का अर्थ केवल कम भोजन करना नहीं, बल्कि सभी आवश्यक पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सेवन करना है। महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन: शरीर की मरम्मत और शक्ति के लिए आयरन: रक्त की कमी से बचाव हेतु कैल्शियम एवं विटामिन डी: हडिड्यों और दाँतों के लिए फोलिक एसिड एवं विटामिन बी: तंत्रिका तंत्र और हार्मोन संतुलन के लिए रेशा (फाइबर): पाचन तंत्र और वजन नियंत्रण के लिए दालें, हरी सब्जियाँ, फल, दूध-दही, मेवे और बीज भारतीय आहार में पोषण के उत्तम स्रोत हैं। जीवनशैली की भूमिका स्वस्थ जीवन के लिए केवल अच्छा भोजन ही पर्याप्त नहीं है। जीवनशैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित और पर्याप्त नींद प्रतिदिन हल्का व्यायाम या योग तनाव प्रबंधन पर्याप्त जल सेवन समय पर भोजन छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव दीर्घकाल में बड़े लाभ प्रदान करते हैं। स्व-देखभाल: स्वार्थ नहीं, आवश्यकता अनेक महिलाएँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को स्वार्थ समझती हैं, जबकि वास्तव में यह एक आवश्यकता है। नियमित स्वास्थ्य जाँच, शरीर के संकेतों को समझना और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है।

महिला स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ विषय है। उचित पोषण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देती है। अतः समाज के प्रत्येक स्तर पर महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समय की माँग है।

राज्य की संस्कृति और शिल्प को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में उकेरती श्रद्धा नेगी

श्रद्धा नेगी उत्तराखंड की संस्कृति, शिल्प और शांत विलासिता पर आधारित भारत का पहले डिज़ाइन-आधारित जीवनशैली ब्रांड जूसीवर्स की संस्थापक है। यह ब्रांड उत्तराखंड की महिलाओं का एक सशक्त समूह तैयार कर राज्य की कहानियों, संस्कृति और शिल्प को समकालीन स्वरूप में दुनिया तक पहुँचाने का कार्य कर रही है।

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए।

मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जिसकी जड़ें सैन्य परंपरा से जुड़ी हैं। मेरे परदादा से लेकर दादा, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने देशसेवा की यह विरासत चली आ रही है। इस वातावरण में पले-बढ़े होने के कारण अनुशासन, आत्मबल, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्य स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ और देहरादून मेरी कर्मभूमि और आत्मिक जुड़ाव का केंद्र रहा है। शैक्षणिक रूप से मैं वर्ष 2002 बैच की एनआईएफटी एलुमनी हूँ और मैंने एनआईएफटी हैदराबाद से टेक्सटाइल डिजाइन एंड डेवलपमेंट में पोस्टग्रेजुएशन किया है। इसके अतिरिक्त, फैशन डिजाइन में डिप्लोमा और विभिन्न सर्टिफिकेशन ने मेरे प्रोफेशनल सफर की एक मजबूत नींव रखी।

अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में बताइए, आप इस क्षेत्र में कैसे आई और किससे प्रेरणा मिली?

मेरे करियर की शुरुआत एक टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में हुई लेकिन उद्यमिता में मेरा प्रवेश किसी पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा नहीं था। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान, जब पूरी दुनिया ठहर गई, तब मैंने अपने जीवन और कार्य के वास्तविक उद्देश्य पर गहराई से आत्ममंथन किया। उस समय मैं ऋतु कुमार ब्रांड में होम डिवीजन का नेतृत्व कर रही थी। वैश्विक अनिश्चितता और निजी जीवन में आए परिवर्तनों ने मुझे एक सुरक्षित कॉर्पोरेट भूमिका से बाहर निकलकर अपने इकिगाई-अपने जीवन के उद्देश्य-का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। मैं देहरादून लौट आई और यहीं से मेरी स्वतंत्र यात्रा की शुरुआत हुई। कोविड मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ,जहाँ एक नौकरीपेशा पेशेवर से मैं स्वरोजगार की ओर बढ़ी और फिर दूसरों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कदम रखा।

अब तक की आपकी प्रमुख उपलब्धियाँ और कार्य कौन-से रहे हैं?

मेरी पेशेवर यात्रा एक सशक्त शैक्षणिक आधार और दो दशकों से अधिक के इंडस्ट्री अनुभव से निर्मित हुई है। एनआईएफटी में मुझे बेस्ट ग्रैजुएशन प्रोजेक्ट का सम्मान प्राप्त हुआ, जिसने मेरे आत्मविश्वास को और मजबूत किया। पेशेवर स्तर पर, मुझे ज़ारा होम, पोट्री बार्न, सरिता हांडा और ऋतु कुमार जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ काम करने का अवसर मिला, जहाँ आगे चलकर मैंने होम डिवीजन का नेतृत्व भी किया। मेरी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इकिगाई डिजाइन्स की स्थापना है-एक B2B डिजाइन और कंसल्टिंग कंपनी, जो कॉन्सेप्ट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक की संपूर्ण प्रक्रिया को संभालती है। इसी के अंतर्गत मैं 'जूसीवर्स' जैसे कंज्यूमर ब्रांड्स का भी विकास कर रही हूँ। इकिगाई डिजाइन्स स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परियोजना में 48 कमरों के इंटीरियर और कस्टम उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत करना मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा। देहरादून के मालसी, राजपुर रोड स्थित एड्स वन मॉल में अपना रिटेल स्पेस स्थापित करना, उन्हू कम्युनिटी से वूमैन एंटरनप्रयोनर ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त करना, और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर वंचित महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना ये सभी मेरे सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं।

आपकी भविष्य की योजनाएँ क्या हैं?

मेरी भविष्य की योजनाएँ उत्तराखंड से जुड़ा एक ऐसा वैश्विक ब्रांड स्थापित करने पर केंद्रित हैं, जो डिजाइन और उत्पादों के माध्यम से राज्य की कहानियों, संस्कृति और शिल्प को समकालीन स्वरूप में दुनिया तक पहुँचाए। इसके साथ ही, मैं महिलाओं के लिए एक सशक्त समुदाय बनाने की दिशा में भी कार्यरत हूँ- जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग, साझा विकास और आपसी समर्थन को प्राथमिकता दी जाए।

हमारी पत्रिका के माध्यम से आप पाठ्कों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

इस मंच के माध्यम से मैं पाठ्कों को जूसीवर्स ट्राइब का हिस्सा बनने का आमंत्रण देना चाहती हूँ, एक ऐसा समुदाय जो आत्मसम्मान, सच्चाई और शांत आत्मबल पर आधारित है। यह उन महिलाओं के लिए है जो प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग को चुनती हैं। लंबे समय तक महिलाओं को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया गया है, लेकिन अब समय है इस सोच को बदलने का। जब महिलाएँ साझा उद्देश्य और ईमानदारी के साथ एकजुट होती हैं, तो उनकी सामूहिक शक्ति किसी भी व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब महिलाएँ साथ उठती हैं, तो वे सिर्फ आगे नहीं बढ़तीं वे और भी मजबूत बनती हैं और जब एक महिला अपनी कहानी, संस्कृति और अनुभव साझा करती है, तो दुनिया उसे सुनने लगती है।

समाज में समानता को कमजोर करने की कोशिश

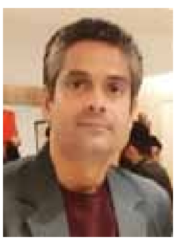

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

देश में सामाजिक समानता और समरसता की बात करने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में यूजीसी द्वारा लाया गया नया नियम अब बड़े सवालों के घेरे में आ गया है। जिस नियम को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर पेश किया गया, वही नियम देखते-ही-देखते समाज में असमानता और विभाजन की बहस का केंद्र बन गया। इस फैसले ने न केवल स्कूल-कॉलेजों से जुड़े शिक्षाविदों को चौंकाया, बल्कि समाज के सवर्ण वर्ग में गहरी नाराजगी भी पैदा कर दी। यूजीसी के इस नियम के खिलाफ सबसे तीखी प्रतिक्रिया सवर्ण समाज की ओर से देखने को मिली। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों तक विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कों पर नारे गूंजे और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग उठी। विरोध का सबसे प्रतीकात्मक और चौंकाने वाला कदम तब सामने आया, जब उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देकर अपना आक्रोश सार्वजनिक किया। भाजपा के अधिकांश नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। विपक्ष ने इसे सरकार की चुप्पी बताया, जबकि सवर्ण समाज ने इसे अनदेखी और असंवेदनशीलता करार दिया। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने यूजीसी के इस नियम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की। हालांकि अदालत की रोक के बावजूद, सवर्ण समाज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इसका साफ असर दिख रहा है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत सामाजिक समरसता होती है। विविधताओं से भरे देश में विचारों का टकराव स्वाभाविक है, लेकिन नीतियों का उद्देश्य जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। ऐसे समय में, जब सत्तारूढ़ दल स्वयं "कटोगे तो बंटोगे" जैसे नारों के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश देने की बात करता है, उसी दौर में शिक्षा से जुड़े एक फैसले ने देश के एक बड़े वर्ग के भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर दी। यह बेचैनी केवल किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे राष्ट्रीय बहस का रूप लेती चली गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 13 जनवरी को लागू किए गए नए नियम को लेकर सबसे अधिक प्रतिक्रिया सवर्ण समुदाय की ओर से सामने आई। इस फैसले को लेकर यह धारणा बनने लगी कि शिक्षा संस्थानों में समान अवसर की भावना कमजोर हो सकती है। समाज के उस हिस्से ने, जो खुद को लंबे समय से मुख्यधारा का सहभागी मानता रहा है, इस कदम को असंतुलित और जल्दबाजी भरा बताया। कई लोगों का कहना है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक विमर्श, सामाजिक प्रभाव का आकलन और जमीनी हकीकत की पड़ताल जरूरी होती है, जो इस मामले में दिखाई नहीं दी। जैसे-जैसे यह नियम स्कूलों और महाविद्यालयों में लागू होने लगा, वैसे-वैसे असंतोष खुलकर सामने आने लगा। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी हिस्सों तक, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। शांतिपूर्ण सभाओं

से लेकर ज्ञापन सौंपने तक, नाराजगी के अलग-अलग रूप दिखे। प्रदर्शनकारियों का तर्क साफ था कि बिना पर्याप्त अध्ययन के लिया गया फैसला शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। उनका मानना था कि नीति निर्धारण में जल्दबाजी भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया एक घटनाक्रम चर्चा का केंद्र बन गया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं माना गया, बल्कि इसे वैचारिक असहमति के प्रतीक के रूप में देखा गया। उनके इस कदम ने यह संकेत दिया कि असंतोष केवल सड़क तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था के भीतर बैठे जिम्मेदार अधिकारी भी इस निर्णय से असहज महसूस कर रहे हैं। उनके इस्तीफे ने बहस को और तेज कर दिया तथा इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर नई धार दी। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई। इतना व्यापक सामाजिक उबाल होने के बावजूद, सत्ताधारी दल के अधिकांश नेता सार्वजनिक रूप से इस विषय पर बोलने से बचते दिखाई दिए। न समर्थन में स्पष्ट बयान आया, न ही असहमति में। इस चुप्पी को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या यह संवेदनशील मुद्दा राजनीतिक असहजता पैदा कर रहा है, या फिर इसे समय के साथ ठंडा पड़ने देने की रणनीति अपनाई गई है। विपक्षी दलों ने इस मौन को सरकार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश बताया, जबकि आंदोलनरत लोगों ने इसे अनदेखी की संज्ञा दी। मामला धीरे-धीरे न्यायिक दायरे में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने इस विवाद को कानूनी मंच पर ला खड़ा किया। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने प्रारंभिक दृष्टि में इस नियम के प्रभावों पर गंभीर सवाल उठाए और तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा से जुड़े किसी भी बदलाव का समाज पर दूरगामी असर पड़ता है, इसलिए हर पहलू की बारीकी से जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई, जिससे यह साफ हो गया कि यह मामला जल्द खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि न्यायालय के इस हस्तक्षेप से अस्थायी राहत जरूर मिली, लेकिन सामाजिक असंतोष पूरी तरह शांत नहीं हुआ।

यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में किए गए दो अहम बदलावों ने नए विवाद को जन्म दे दिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। कमोबेश देश भर के हायर एजुकेशन सिस्टम को यही आयोग कंट्रोल करता है। 12वीं के बाद जो भी छात्र ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई के लिए एनरॉल होते हैं, उन्हें इसके नियमों से सामना होता है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जन जाति (एसटी) के छात्रों के लिए यूजीसी ने कुछ खास नियम बना रखे हैं। कॉलेज में इसका पालन जरूरी होता है। पहली बार वही नियम ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की जातियों से आने वाले छात्रों को शामिल किया गया है। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में दो अहम बदलाव किए हैं, सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी से आने छात्रों के साथ भेदभाव बताया जा रहा है। तकरीबन पूरे देश में इसका विरोध हुआ। उनका मानना है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी भर के होने से ही वो दोषी हो जाएंगे। सरकार की ओर से कोई बड़ा नेता इस मसले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और जिस यूजीसी ने इस नियम को लागू किया है, उसके चेयरमैन विनीत जोशी हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को नई नियमावली लागू की। 15 जनवरी से प्रभावी हुए इन नियमों का उद्देश्य एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्रों और शिक्षकों के लिए परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। नियम के मुताबिक जाति-आधारित भेदभाव इससे समाप्त होगा। हालांकि, इन नियमों ने आरक्षण जैसे एक नए विवाद को जन्म दे दिया। सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने इसे 'सामान्य वर्ग विरोधी' करार देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विवाद का मुख्य केंद्र झूठी शिकायतों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटाना और सवर्णों को इस सुरक्षा चक्र से बाहर रखना है। यूजीसी ने 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026' के तहत हर संस्थान में समान अवसर केंद्र और इक्विटी समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया है। इसमें पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है। इन नियमों के अनुसार, किसी भी संस्थान के प्रमुख (कुलपति या प्राचार्य) को भेदभाव के खिलाफ सीधे जवाबदेह बनाया गया है।

सवर्ण समुदाय के भीतर यह भावना बनी रही कि सरकार और संबंधित संस्थान ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। कई लोगों का कहना है कि अदालत की रोक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि केवल एक विराम है। मूल सवाल अब भी जस का तस खड़ा है- क्या शिक्षा नीति बनाते समय सामाजिक संतुलन को पर्याप्त महत्व दिया गया? डिजिटल मंचों पर भी इस नाराजगी की गूंज साफ सुनाई दी। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट, टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं। अलग-अलग विचारधाराओं के लोग इस विषय पर खुलकर अपनी राय रखते नजर आए। कहीं इसे समानता के सिद्धांत पर चोट बताया गया, तो कहीं इसे नीति निर्माण की प्रक्रिया में संवाद की कमी

का परिणाम कहा गया। हैशटैग के जरिए विरोध दर्ज कराया गया और कई वीडियो संदेशों में युवाओं ने भविष्य को लेकर अपनी आशंकाएं साझा कीं। शिक्षाविदों के एक वर्ग ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। उनका मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या प्रवेश प्रक्रिया तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज की दिशा तय करने वाला माध्यम है। ऐसे में किसी भी नियम का प्रभाव केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सोच, अवसर और सहभागिता को भी प्रभावित करता है। उनका तर्क है कि यदि किसी निर्णय से समाज के किसी हिस्से में अलगाव की भावना जन्म लेती है, तो उस पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। इस विवाद ने यूजीसी की कार्यप्रणाली पर भी रोशनी डाली। आरोप लगे कि नियम को लागू करने से पहले न तो राज्यों से पर्याप्त सलाह ली गई, न ही शिक्षण संस्थानों से व्यापक फीडबैक हासिल किया गया। कई कॉलेज प्रशासन इस बदलाव को लेकर असमंजस में दिखे। कुछ जगहों पर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जबकि कई संस्थान स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में प्रतीक्षा की स्थिति में थे। इस अव्यवस्था ने भी असंतोष को और गहरा किया। समाज के व्यापक हित की बात करें तो यह पूरा मामला एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। नीतियां यदि लोगों को साथ लेकर नहीं चलतीं, तो उनका विरोध होना तय है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में शिक्षा से जुड़ा हर फैसला सामाजिक ताने-बाने से जुड़ा होता है। ऐसे में संवाद, पारदर्शिता और अध्ययन की भूमिका और भी बढ़ जाती है। केवल प्रशासनिक आदेशों के जरिए जटिल सामाजिक सवालों का समाधान संभव नहीं हो पाता। फिलहाल स्थिति यह है कि नियम पर रोक लगी हुई है, बहस जारी है और समाज के अलग-अलग वर्ग अपनी-अपनी आशंकाओं के साथ सामने हैं। सरकार, यूजीसी और अन्य संबंधित संस्थानों के सामने यह चुनौती है कि वे इस मुद्दे को टकराव के बजाय संवाद के रास्ते से सुलझाएं। यदि वास्तव में लक्ष्य सामाजिक एकता और समान अवसर है, तो नीति निर्माण की प्रक्रिया में सभी पक्षों को भरोसे में लेना ही एकमात्र रास्ता है। आखिरकार, शिक्षा का उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना होता है, न कि विभाजन की रेखाएं खींचना। इस पूरे प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले न केवल व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और यूजीसी इस अनुभव से क्या सीख लेते हैं और क्या भविष्य की नीतियां वास्तव में जोड़ने वाली साबित होंगी।

यूजीसी के नए नियम को लेकर सवर्ण समाज का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा

यूजीसी के नए नियम को लेकर उठे विवाद ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि आखिर मोदी सरकार की भूमिका क्या रही। क्या यूजीसी ने यह नियम पूरी तरह स्वायत्त रूप से बनाया या फिर इसके पीछे सरकार की सहमति और दिशा-निर्देश भी शामिल थे। चूंकि यूजीसी केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला निकाय है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल सरकार तक पहुंचता है। विरोध करने वाले वर्गों का कहना है कि यदि सरकार समय रहते इस पर हस्तक्षेप करती और व्यापक विमर्श कराती, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। सामाजिक दृष्टि से देखें तो भाजपा के लिए यह मुद्दा असहज करने वाला साबित हुआ है। इतना बड़ा सामाजिक विवाद होने के बावजूद पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट और ठोस बयान सामने नहीं आया। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, या फिर यह मान लिया गया है कि समय के साथ विरोध की तीव्रता कम हो जाएगी। हालांकि सवर्ण समाज के भीतर यह भावना गहराती जा रही है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे मामले में निर्णायक मोड़ लेकर आया। अदालत ने भेदभाव से जुड़े रेगुलेशन पर रोक लगाते हुए यह साफ संकेत दिया कि शिक्षा नीति से जुड़े फैसलों में संवैधानिक मूल्यों और समान अवसर की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी को सरकार और यूजीसी दोनों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अगली सुनवाई की तारीख तय होने के बाद अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सवर्ण समाज से जुड़े कई संगठनों और युवाओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए हैं कि क्या यह नियम किसी खास वर्ग को निशाना बनाकर बनाया गया। पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियों के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि यदि सरकार ने समय रहते भरोसा बहाल नहीं किया, तो इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। सबसे अहम सवाल अब आने वाले चुनावों को लेकर उठ रहा है। क्या यह मुद्दा भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सवर्ण वोट बैंक को भाजपा का पारंपरिक समर्थन माना जाता रहा है। यदि इस वर्ग के भीतर नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल एक मुद्दा चुनाव परिणाम तय करेगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे फैसले सरकार की छवि को प्रभावित करते हैं। मोदी सरकार की राजनीति अब तक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक फैसलों की रही है, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी का आरोप उस छवि को चुनौती देता है। विरोध करने वालों का कहना है कि यदि सरकार "सबका साथ, सबका विकास" की बात करती है, तो नीति निर्माण में भी उसी भावना का पालन होना चाहिए। शिक्षा जैसे क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले सामाजिक संतुलन, समानता और संभावित टकरावों पर गंभीरता से विचार जरूरी है। फिलहाल स्थिति यह है कि नियम पर रोक लगी हुई है, असंतोष पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और सरकार की अगली रणनीति पर सबकी नजर है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मोदी सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करती है, यूजीसी को व्यापक अध्ययन के निर्देश देती है और संवाद के जरिए भरोसा बहाल करने की कोशिश करती है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती के रूप में भी सामने आ सकता है।

देवभूमि में यूसीसी से सामाजिक न्याय का नया अध्याय

उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करके देश के संवैधानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय केवल एक कानून की घोषणा नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और पारदर्शी शासन को स्थापित करने का ठोस कदम है। यूसीसी के लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नए मानक स्थापित किए हैं। अब प्रदेश की मुस्लिम बहनों और बेटियों को हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री धामी ने इस कानून को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारकर यह साबित किया कि मजबूत फैसले देश को जोड़ते हैं। बीते एक वर्ष में राज्य में विवाह पंजीकरण की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत दंपतियों का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यूसीसी ने सभी धर्मों के लोगों के विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े नियमों को एक समान किया है। बच्चों के अधिकार, संपत्ति में समानता और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से नागरिकों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। यह कानून किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर समानता और समरसता स्थापित करने का प्रयास है। उत्तराखंड का यह मॉडल आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

उत्तराखंड ने मंगलवार को अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रथम "समान नागरिक संहिता दिवस" मनाया। हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन प्रदेश के लिए स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा।उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की वास्तविक स्थापना का प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों, प्रभावी क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने वाले वीएलसी को सम्मानित किया। इस अवसर पर यूसीसी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया, जिसने कानून के ऐतिहासिक महत्व और सामाजिक बदलाव को बखूबी प्रदर्शित किया। सीएम धामी ने कहा कि यह दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा क्योंकि इसी दिन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई। इससे समाज में समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की वास्तविक स्थापना सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव समरसता और समानता की संवाहक रही है। गीता में भी समानता का संदेश दिया गया है, और यही सनातन संस्कृति की महानता है जिसने सदियों से दुनिया को न्याय और मानवता का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं ने देखा था। उनका मानना था कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने दृष्टिपत्र में राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया। जनता ने इस "देवकार्य" के लिए भाजपा को अपार समर्थन और आशीर्वाद प्रदान किया। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही यूसीसी लागू करने का कार्य शुरू किया। 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 27 जनवरी 2025 को यह कानून विधिवत लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से राज्य में महिला सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत हुई है। अब मुस्लिम बहनों और बेटियों को हलाला, इद्दत,

संशोधन के मुख्य प्रावधान और प्रमुख सुधार

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू। धारा 12 के अंतर्गत ''सचिव'' के स्थान पर ''अपर सचिव'' को सक्षम प्राधिकारी नामित। उप-पंजीयक द्वारा समय-सीमा में कार्यवाही न होने पर प्रकरण स्वतः पंजीयक एवं पंजीयक जनरल को अग्रेषित। उप-पंजीयक पर लगाए गए दंड के विरुद्ध अपील का अधिकार तथा दंड की वसूली भू-राजस्व की भांति। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार। विवाह एवं लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी या विधि-विरुद्ध कृत्यों पर कठोर दंड। लिव-इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी। अनुसूची-2 में ''विधवा'' शब्द के स्थान पर ''जीवनसाथी'' शब्द का प्रतिस्थापन। विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध एवं उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को। इन संशोधनों का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट, प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाना, प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में एक भी हलाला या बहुविवाह का मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी लागू करने का साहस नहीं दिखाया गया, जबकि दुनिया के विकसित देशों और प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में यह पहले से लागू है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को समाप्त कर सभी नागरिकों में समानता और समरसता स्थापित करने का कानूनी प्रयास है। कानून में विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, संपत्ति बंटवारा और बच्चों के अधिकारों से जुड़े नियम सभी के लिए समान हैं। लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है, और इसके दौरान जन्मे बच्चों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने घोषणा से लेकर प्रभावी क्रियान्वयन तक यूसीसी को लागू किया। बीते एक वर्ष में राज्य में विवाह पंजीकरण औसतन 67 से बढ़कर प्रतिदिन 1400 से अधिक हो गया है। लगभग 30 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत दंपतियों का पंजीकरण पूरा हुआ। यूसीसी के तहत लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। 7500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासन सीधे जनता के द्वार तक पहुंचा है। हाल ही में यूसीसी में आवश्यक संशोधनों के तहत विधेयक पारित हुआ, जिसमें विवाह के समय पहचान छिपाने या गलत तथ्य देने पर विवाह को निरस्त करने का प्रावधान शामिल है। साथ ही किसी भी प्रकार के बल, दबाव या धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय देश को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प आज सिद्धि बन चुके हैं। कुछ लोग यूसीसी को लेकर भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल सामाजिक न्याय और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड से निकलने वाली यह "यूसीसी धारा" अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। उन्होंने कहा कि बहुविवाह और विवाह विच्छेद के मामलों में सख्ती की जाएगी और कानून के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, सविता कपूर, सुरेश गड़िया, बृज भूषण गैरोला, सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, यूसीसी समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह, दून विवि की वीसी सुरेखा डंगवाल, मनु गौड़, अजय मिश्रा, विशेष सचिव गृह निवेदिता कुकरेती और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश 2026 लागू

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 में आवश्यक संशोधनों हेतु समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल उत्तराखण्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा जारी किया गया है। अध्यादेश के माध्यम से संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक एवं दंडात्मक सुधार किए गए हैं, जिससे समान नागरिक संहिता के प्रभावी, पारदर्शी एवं सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

सोना-चांदी की भारी गिरावट ने बाजार को हिलाया

शुक्रवार, 30 जनवरी को सोना और चांदी के बाजार में अचानक भारी हलचल देखने को मिली। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने में करीब 1,65,795 रुपए से घटकर 1,49,075 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी लगभग 16,700 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी का भाव 2,91,922 रुपए प्रति किलो तक फिसल गया, जो पिछले स्तर से लगभग 1 लाख रुपए कम है। डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक मुनाफावसूली की तेज गतिविधियों के चलते कीमती धातुओं के दाम अचानक धराशायी हो गए। बाजार में हाहाकार मच गया, अरबों रुपए के निवेशकों की पोजिशनें कमजोर पड़ गई, और कई मुनाफाखोरों को बेचने को मजबूर होना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऐतिहासिक गिरावट केवल एक जरूरी सुधार प्रक्रिया है, जिससे भविष्य में बाजार अधिक स्थिर होकर आगे बढ़ सकता है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

शुक्रवार, 30 जनवरी का दिन सोने और चांदी के निवेशकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। सुबह के शुरुआती घंटों में ही एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोने और चांदी के भाव में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। फरवरी डिलीवरी वाले सोने का भाव 1,65,795 रुपए से गिरकर 1,49,074 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया, यानी लगभग 16,700 रुपए की ऐतिहासिक कमी। चांदी का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। मार्च डिलीवरी वाली चांदी लगभग 2,91,922 रुपए प्रति किलो तक फिसल गई, जो पिछले स्तर से लगभग 1 लाख रुपए कम है। इस अचानक आई गिरावट ने निवेशकों और मुनाफाखोरों की नींद उड़ा दी। कई निवेशक, जिन्होंने सोना और चांदी में लीवरेज्ड पोजिशन बनाई थी, डर और दबाव में अपनी पोजिशनें बंद करने को मजबूर हो गए। अरबों रुपए का मार्केट वैल्यू मिनटों में घट गया और बाजार में हड़कंप मच गया। विशेषज्ञों ने इसे "ऐतिहासिक गिरावट" बताया और कहा कि ऐसे उतार-चढ़ाव निवेशकों को सावधान रहने का सख्त संदेश देते हैं। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर का मजबूती से उभार और वैश्विक मुनाफाखोरी की तेज गतिविधियां हैं। डॉलर के मजबूत होने का असर सोने और चांदी के भाव पर तुरंत पड़ा, क्योंकि ये धातुएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में ट्रेड होती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य मुद्राओं में सोने-चांदी की कीमतें बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिससे निवेशक तेजी से बेचने लगते हैं। इस बार की गिरावट को और भी गहरा करने वाली वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन केविन वार्श को लेकर बढ़ती उम्मीदें हैं। वार्श को महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त रुख अपनाने वाला माना जाता है। उनका यह रुख निवेशकों के लिए यह संकेत देता है कि अमेरिकी ब्याज दरें लंबे समय तक कम नहीं रहेंगी। इससे सोने और चांदी में मुनाफाखोरों ने तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, वास्तविक बॉन्ड यील्ड बढ़ीं, और सोने व चांदी में लीवरेज्ड पोजिशन, जिन्हें करेंसी वैल्यू घटने से बचाव के तौर पर लिया गया था, तेजी से खत्म कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में अचानक बिकवाली का तूफान आया और अरबों डॉलर का मार्केट वैल्यू मिनटों में साफ हो गया। कई छोटे और कमजोर निवेशक, जो पहले बाजार में तेजी का फायदा उठाने के लिए लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे थे, भारी नुकसान के डर से बेचने को मजबूर हुए। आईबीजेए (इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) के आंकड़े बताते हैं कि 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर घटकर 1,65,795 रुपए रह गया। इससे पहले यह भाव 1,75,340 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं चांदी में भी निवेशकों को झटका लगा। मार्च डिलीवरी वाली चांदी का भाव लगभग 2,91,922 रुपए प्रति किलो तक फिसला। विशेषज्ञों ने कहा कि इस गिरावट का असर केवल "शॉर्ट-टर्म थकावट" का संकेत देता है, न कि लंबे समय की मंदी (बेयर मार्केट) की शुरुआत। लंबी अवधि के बुनियादी कारक अब भी मजबूत बने हुए हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद जारी है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से चांदी की औद्योगिक मांग तेजी से बढ़ रही है। इन वजहों से चांदी की आपूर्ति में संरचनात्मक कमी बनी हुई है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि में सोना और चांदी का निवेश फायदेमंद बना रहेगा। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि इस समय डर के चलते जल्दी निर्णय लेने की बजाय धैर्य और रणनीति के साथ कदम रखें। बाजार में यह गिरावट एक तरह की जरूरी सुधार प्रक्रिया है। जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी और जोखिम भरे निवेश बाहर निकल गए हैं, जिससे आगे चलकर बाजार अधिक स्थिर और नियंत्रित होकर ऊपर जा सकता है। यदि चांदी की कीमत 3 लाख से 3.10 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर आती है, तो यह निवेशकों के लिए दोबारा खरीदारी का अवसर बन सकता है। इससे चांदी की कीमत संभावित रूप से 3.40 लाख से 3.50 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। सोने के लिए भी विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है, खासकर वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति के दबाव के चलते। निवेशक और मुनाफाखोर अब इस गिरावट को "सुनहरा अवसर" के तौर पर देख रहे हैं। कई बड़े निवेशक इसे बाजार में उचित एंट्री पॉइंट मान रहे हैं, जबकि छोटे निवेशक अचानक आई गिरावट से डर गए हैं और अपने निवेश निकाल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया बाजार को अधिक स्वस्थ और नियंत्रित बनाने में मदद करेगी। भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स का भी असर पड़ा है। अमेरिका में डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की नीति का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। डॉलर मजबूत

होने पर सोना और चांदी भारतीय रुपये में महंगे प्रतीत होते हैं, जिससे निवेशक तेजी से बेचने लगते हैं। इस गिरावट के बावजूद लंबे समय में कीमती धातुओं का महत्व कम नहीं हुआ है। सोना और चांदी की औद्योगिक और निवेश दोनों ही मांग मजबूत बनी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और आर्थिक उतार-चढ़ाव के समय निवेशक अक्सर सोना और चांदी को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। शुक्रवार को हुई यह ऐतिहासिक गिरावट यह दर्शाती है कि बाजार में सट्टा और मुनाफाखोरी के कारण अचानक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में बाजार फिर से सुधरकर और नियंत्रित होकर अपने पुराने स्तरों से ऊपर जा सकता है। सोना और चांदी में शुक्रवार को आई भारी गिरावट न केवल निवेशकों को चेतावनी देती है, बल्कि भविष्य में संभावित अवसरों के लिए दरवाजा भी खोलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेशक सही समय पर समझदारी से निवेश करें, तो लंबी अवधि में उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भारतीय बाजार में मचाई हलचल

जनवरी महीने में चांदी ने करीब 42 फीसदी की छलांग लगाई थी, जो किसी एक महीने में इसमें आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है। वहीं सोने का भाव डॉलर के टर्म्स में 15 फीसदी से अधिक बढ़ा, जो 1999 के बाद की सबसे बड़ी मंथली तेजी थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 5,594 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छू गया, जबकि चांदी 121 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई। इतनी तेज रफ्तार से कीमतों का बढ़ना संकेत था कि बाजार काफी हद तक ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका से आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह जल्द ही फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के उत्तराधिकारी का नाम घोषित करेंगे। बाजार में यह चर्चा तेज हो गई कि फेडरल रिजर्व का अगला अध्यक्ष हॉकिश रुख अपना सकता है। इसका मतलब निकाला गया कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं और मॉनिटरी पॉलिसी के नरम होने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। इस खबर के बाद अमेरिकी डॉलर में मजबूती देखी गई। डॉलर इंडेक्स करीब 0.4 फीसदी चढ़कर 96.60 के स्तर पर पहुंच गया। मजबूत डॉलर का असर सीधे तौर पर सोने और चांदी पर पड़ा, क्योंकि ये डॉलर में कीमत तय होने वाली कमोडिटी हैं। डॉलर मजबूत होने पर दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए ये महंगी हो जाती हैं, जिससे बिकवाली बढ़ती है। जब बाजार पहले से ओवरबॉट हो और ऐसी खबर आए, तो मुनाफावसूली तेज हो जाती है। यही वजह रही कि निवेशकों ने ऊपरी स्तरों पर तेजी से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ज्यादातर कमोडिटी एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स इस सवाल पर सहमत नहीं हैं कि तेजी खत्म हो चुकी है। उनका मानना है कि आज की गिरावट को एक नॉर्मल करेक्शन की तरह देखा जाना चाहिए। गोल्ड के भाव में लगातार छह महीनों से तेजी रही है, जबकि सिल्वर का भाव नौ महीने से लगातार ऊपर जा रहा था। इतने लंबे समय की तेजी के बाद थोड़ा ठहराव या गिरावट बाजार की सेहत के लिए जरूरी माना जाता है। लॉन्ग-टर्म फंडामेंटल अब भी मजबूत हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई और डेटा सेंटर्स में सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीद जारी रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समय न तो घबराकर बेचने का है और न ही एकमुश्त खरीदारी करने का। कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए सलाह है कि गोल्ड और सिल्वर मिलाकर कुल पोर्टफोलियो का 5-10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा न रखें। सिल्वर ज्यादा वोलाटाइल हो चुकी है, जबकि गोल्ड तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह समय जोखिम भरा है, क्योंकि थोड़ी सी खबर पर कीमतों में बड़ी हलचल हो सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। गोल्ड और सिल्वर में आई यह गिरावट डरने की वजह नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले लेने का समय है। लॉन्ग टर्म में इनकी कहानी मजबूत बनी हुई है, लेकिन जल्दबाजी भारी नुकसान करा सकती है।

देवभूमि में कश्मीरी फेरीवालों से मारपीट से सवालों के घेरे में समाज

देवभूमि उत्तराखंड में कश्मीरी फेरी वालों के साथ हुई मारपीट की घटना ने एक बार फिर समाज के सामने गंभीर और असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। रोजी-रोटी की तलाश में देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए युवकों से नाम, धर्म और क्षेत्रीय पहचान पूछकर की गई हिंसा न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है, बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने को भी झकझोरती है, जिस पर उत्तराखंड की शांति और सहअस्तित्व की परंपरा टिकी रही है। यह घटना बताती है कि किस तरह अफवाह, नफरत और भय का माहौल आम नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। इसके उलट दुकानदार महिला ने दो युवकों पर बदतमीजी करने, गाली गलौच करने, भद्दे इशारे करने और दुकान पर जबरन झगड़ा करने का मुकद्मा दर्ज कराया है। जब बाजार, जो आपसी मेल-मिलाप का प्रतीक होता है, वहां इस तरह की घटना पूरे समाज के लिए चेतावनी है। जरूरी हो गई है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

देवभूमि उत्तराखंड, जिसे सदियों से शांति, सहिष्णुता और अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाना जाता है, वहां कश्मीरी फेरी वालों के साथ सामने आ रही मारपीट की घटनाएं समाज की संस्कृत छवि पर सवाल खड़े कर रही हैं। ताजा मामला देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां दो कश्मीरी मुस्लिम युवकों के साथ कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट की गई। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक फेरी लगाकर शॉल बेचने का काम करते हैं और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए विकासनगर बाजार के डाक पत्थर रोड स्थित एक दुकान पर गए थे। आरोप है कि सामान खरीदते समय दुकानदार ने उनसे पहले नाम और धर्म के बारे में पूछा। युवक ने अपना नाम दानिश बताया और

अब रीना यादव ने कराया मुकद्मा: रीना ने आरोप लगाया कि 'दो युवकों ने दुकान पर आकर नमकीन मांगी, लेकिन मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आई, तो उन्होंने मुझे भद्दे इशारे किए, विरोध करने पर गाली दी और हाथ पकड़ा। पीछे से मेरे पति आए उन्होंने दोनो युवको को धमकाया और वहां से जाने के लिए कहा लेकिन दोनों युवकों ने उलटा उनके साथ बदसलूकी की। इसी टकराव में मेरे पति और उन दोनों युवकों का झगड़ा हो गया। हमें नहीं पता था कि वे कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं।'

मुस्लिम होने की बात कही। इसके बाद जब उनसे उनके मूल स्थान के बारे में सवाल किया गया और उन्होंने कश्मीर से आने की जानकारी दी, तो दुकानदार ने कथित तौर पर आपत्तिजनक धार्मिक और जातिगत टिप्पणियां शुरू कर दीं। पीड़ित युवकों का आरोप है कि बात यहीं नहीं रुकी। दुकानदार ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर फैलते ही इलाके का माहौल गरमा गया। समुदाय विशेष के लोग मौके पर एकत्र हुए और घायल कश्मीरी युवकों को गोद में उठाकर नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने संयम बरतते हुए शांति बनाए रखी और कानून पर भरोसा जताया। हमले में घायल युवक दानिश ने बताया कि वह दुकान पर नमकीन खरीदने गया था। खरीदारी के बाद उससे नाम, धर्म और कश्मीर से होने को लेकर सवाल किए गए और फिर अचानक मारपीट शुरू हो गई। पीड़ितों के रिश्तेदार अब्दुल राशिद मीर ने बताया कि वे लोग हर साल रोजगार के सिलसिले में उत्तराखंड आते हैं और मार्च तक यहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं 2008 से यहां काम के लिए आते रहे हैं, जबकि ये युवक हाल ही में पहुंचे थे। उनका आरोप है कि धर्म के नाम पर युवकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक का सिर फट गया और दूसरे की बाजू में फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, वे यहां से नहीं जाएंगे। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मोहम्मद इमरान ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में लगातार धर्म के आधार पर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है और कश्मीर से आए युवकों पर जानलेवा हमला इसी का उदाहरण है। मामले पर जानकारी देते हुए विकासनगर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक शीशुपाल राणा ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की तहरीर प्राप्त हुई है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी संजय यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कश्मीरी फेरी वालों और दुकानदार के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद मामले में अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। देवभूमि की पहचान हमेशा से अच्छे व्यवहार, आपसी सम्मान और मानवता की रही है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि समाज को आत्ममंथन करने का अवसर भी देती हैं कि नफरत और पूर्वाग्रह के लिए यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी, सीएम धामी से फोन पर की कड़ी कार्रवाई की मांग

देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा रुख अपनाया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामने आए ताजा मामलों पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीरियों को निशाना बनाना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में एक युवा कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले का जिक्र करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि रोजी-रोटी के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जाने वाले कश्मीरी युवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक पोस्ट में बताया गया कि उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री धामी से इस घटना को लेकर विस्तार से चर्चा की और एफआईआर दर्ज करने सहित कठोर कदम उठाने का आग्रह किया। पोस्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में रह रहे जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता और भी स्पष्ट शब्दों में जाहिर की। उन्होंने लिखा कि जब देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरी लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हों, तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर वास्तव में भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने दो टूक कहा कि जहां भी कश्मीरियों के साथ अन्याय होगा, वहां उनकी सरकार हस्तक्षेप करेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने न केवल कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देश की सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे पर भी चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री का सख्त रुख यह संकेत देता है कि इस मुद्दे को अब केवल स्थानीय घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा।

अब बजट का इम्तिहान उम्मीदें बेहिसाब

रविवार, 1 फरवरी को संसद में पेश होने जा रहा केंद्रीय बजट 2026 सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और चिंताओं का आईना है। यह पहला मौका है जब वर्ष 2017 में बजट की तारीख बदले जाने के बाद किसी रविवार को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में यह दिन न केवल आर्थिक दृष्टि से खास है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी आम जनता के लिए बेहद अहम बन गया है। महंगाई की मार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और घरेलू मांग में सुस्ती के बीच लोग इस बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मध्यम वर्ग की नजरें सबसे ज्यादा कर ढांचे पर टिकी हैं। बीते वर्षों में टैक्स राहत मिलने से उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि इस बार भी सरकार उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। रसोई का बजट, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च और घर खरीदने के सपने, हर उम्मीद किसी न किसी रूप में इस बजट से जुड़ी हुई है। वहीं वेतनभोगी वर्ग यह जानना चाहता है कि क्या बढ़ती महंगाई के मुकाबले उनकी आय को कुछ सहारा मिलेगा या नहीं। किसानों के लिए यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल और सिंचाई जैसे खर्चों में राहत, पीएम-किसान जैसी योजनाओं को मजबूत करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्पष्ट संकेत की आस इस बार ज्यादा दिख रही है। महिलाओं और युवाओं की अपेक्षाएं भी इस बजट से जुड़ी हैं। महिला सशक्तिकरण, रोजगार के नए अवसर, स्टार्टअप्स और शिक्षा पर निवेश जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस पहल की उम्मीद की जा रही है। शंभू नाथ गौतम।

रविवार को संसद में पेश होने जा रहा केंद्रीय बजट 2026 सरकार के लिए एक बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। एक तरफ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का दबाव है, तो दूसरी ओर देश के भीतर महंगाई, रोजगार और आय को लेकर आम लोगों की बढ़ती चिंताएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट भाषण शुरू करेंगी, तो उनकी हर घोषणा पर देश की निगाहें टिकी होंगी। यह बजट न सिर्फ वित्तीय वर्ष 2026-27 की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि सरकार आर्थिक सुस्ती के दौर में आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसान, महिला और युवाओं को कितनी राहत दे पाती है। यह पहला मौका है जब 2017 में बजट की तारीख बदले जाने के बाद रविवार को बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में यह दिन प्रतीकात्मक रूप से भी

खास बन गया है। आमतौर पर छुट्टी का दिन माने जाने वाले रविवार को इस बार देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा खुलेगा। बाजार से लेकर घरों की रसोई तक, बजट को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सवाल एक ही है, क्या इस बार बजट महंगाई के बोझ से राहत देगा या फिर लोगों को और संयम बरतने की सलाह मिलेगी। वर्ष 2026-27 का बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर हालात पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए शुल्क, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। सरकार एक के बाद एक व्यापार समझौतों के जरिए नए बाजार खोलने की कोशिश कर रही है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समझौतों का फायदा तुरंत नहीं दिखता। नए बाजारों में मांग तैयार होने और समझौतों के पूरी तरह लागू होने में समय लगता है। ऐसे में अल्पकालिक चुनौतियां अभी बनी हुई हैं।

बजट में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीदें

इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मध्यम वर्ग को हैं। पिछले वित्त वर्ष के बजट में आयकर में दी गई राहत ने करोड़ों करदाताओं को सुकून दिया था। 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में कटौती और मानक कटौती के बाद 12.75 लाख रुपये तक की कर-मुक्त सीमा ने सरकार को मिडिल क्लास का हितैषी साबित किया था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी टैक्स स्लैब में और बदलाव होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच मिडिल क्लास की क्रय शक्ति दबाव में है। घर का किराया, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च और ईएमआई, हर मोर्चे पर खर्च बढ़ा है। ऐसे में टैक्स में थोड़ी सी भी राहत सीधे लोगों की जेब पर असर डाल सकती है। आम आदमी की नजर सिर्फ टैक्स पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों पर भी है। क्या इस बजट में रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों को काबू में रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों के विस्तार और सब्सिडी को लेकर भी उम्मीदें हैं। वहीं, घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ने की आस है। अगर ऐसा होता है, तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी रफ्तार मिल सकती है, जो रोजगार सृजन के

लिहाज से अहम माना जाता है।

किसान, महिला और युवाओं की परीक्षा

किसानों के लिए यह बजट बेहद अहम है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, खाद-बीज पर सब्सिडी जारी रखने और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्पष्ट और भरोसेमंद नीति की उम्मीद भी किसान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बजट से जुड़े सवाल अलग हैं। क्या महिला उद्यमियों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था होगी। क्या कामकाजी महिलाओं को टैक्स में अतिरिक्त राहत मिलेगी। स्वयं सहायता समूहों और महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या नई योजनाएं आएंगी। वहीं युवाओं की नजर रोजगार पर टिकी है। सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा ऋण पर ब्याज दर में राहत, ये सभी मुद्दे युवाओं के लिए निर्णायक हैं। सरकार का इस बार फोकस 'मेक इन इंडिया' को नई गति देने पर हो सकता है। घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना मौजूदा परिस्थितियों में जरूरी माना जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए एक बड़े रोडमैप की घोषणा की संभावना है। चर्चा है कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बैंकों को वैश्विक टॉप-20 बैंकों में शामिल करने की दिशा में ठोस योजना पेश कर सकती है। इसमें ऑपरेशनल दक्षता, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं पर जोर दिया जा सकता है।

केंद्रीय बजट का संवैधानिक महत्व

केंद्रीय बजट सिर्फ घोषणाओं का दस्तावेज नहीं होता। यह संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद के दोनों सदनों के सामने पेश किया जाता है। इसमें सरकार की अनुमानित आय और खर्च का पूरा ब्योरा होता है। इसके जरिए सरकार अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं और विकास के विजन को स्पष्ट करती है। बजट के बाद ही यह तय होता है कि अगले एक साल में किन क्षेत्रों को ज्यादा संसाधन मिलेंगे और किन योजनाओं पर खास जोर रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पहले ही कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। सबसे लगातार बजट पेश करने और सबसे लंबी बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। लेकिन 2026 का बजट उनके लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक सुस्ती और महंगाई के दौर में पेश हो रहा है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास और राहत के बीच संतुलन साधेंगी। रविवार को पेश होने वाला यह बजट क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दे पाएगा। अगर टैक्स में राहत, सरकारी खर्च में समझदारी और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया गया, तो इसका सीधा असर उपभोग और निवेश पर पड़ेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ सकती है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। रविवार को होने वाला यह बजट सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश का इम्तिहान है। उम्मीदें बेहिसाब हैं, चुनौतियां भी कम नहीं। अब सबकी निगाहें संसद पर टिकी हैं, जहां से यह तय होगा कि आने वाला साल आम आदमी के लिए राहत लेकर आएगा या फिर इंतजार की सूची में एक और साल जुड़ जाएगा।

नरेश बंसल ने उठाया यमुना नदी में नित्य आरती की व्यवस्था का प्रश्न

'सदन मे शून्य काल के माध्यम से राज्यसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉ. नरेश बंसल ने देवभूमि उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन के विकास, यमुना नदी पर घाटों का निर्माण, स्नान व्यवस्था व नित्य आरती का ठोस इंतजाम करने की उठाई मांग।' आज सदन मे शून्य काल के माध्यम से राज्यसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉ. नरेश बंसल ने देवभूमि उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन के विकास व विश्व प्रसिद्ध चारधाम के अलावा राज्य में अन्य स्थानों पर स्थित धार्मिक महत्व के पुरातन मन्दिर श्रृंखला जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से की। डॉ. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधारित पर्यटन है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान होता है। उन्होने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड एक पौराणिक, धार्मिक महत्व प्राकृतिक सौंदर्य के पूर्ण एक अत्यंत सुंदर क्षेत्र है, जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन की हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश करने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है व खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू नदी विभिन्न नदियों को संजोये विदेशी पर्यटकों और अपने देश के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। डॉ. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि यह गंगा स्नान और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। विश्राम और पानी के खेल के लिए भी आदर्श है। यह शहर और क्षेत्र पर्यटकों को ट्रेकिंग, कैम्पिंग और समृद्ध वनस्पतियों की खोज का अवसर प्रदान करता है।

लाखामण्डल, पाताल भुवनेश्वरी आदि प्राचीन गुफायें, शहीद स्मारक व ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है। जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। इसके अलावा कई वाटरफॉल, जगंल और रमणीक स्थल हैं। इसके अलावा काफी पुरातन मन्दिर भी हैं जैसे लाखामण्डल, हनोल, धारी देवी लगभग हर तरफ गांव व शहर में प्राचीन धार्मिक महत्व के चिह्न विराजमान हैं। डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि इसके अलावा माता गंगा पर सभी स्थानों पर धार्मिक महत्व का कार्य जहां संतोषजनक है, वहीं यमुना नदी पर घाटों का निर्माण, स्नान व्यवस्था व नित्य आरती का ठोस इंतजाम होना बाकी है। यहां पर कई पौराणिक महोत्सव, मेले होते हैं जो कि, काफी सालों से पर्यटकों का आकर्षक स्थल बन चुके हैं। डॉ. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि उत्तराखण्ड में ऐसे कई आईडेन्टिफाइड स्थान हैं और अनडेवलप्ड विलेज हैं जिनको हम डेवलप्ड कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के इस रूप के विकास के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन इस देवभूमि उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा। डॉ. नरेश बंसल ने सदन के माध्म से सरकार व मा० पर्यटन मंत्री से आग्रह किया कि, उत्तराखण्ड जो मा० प्रधानमंत्री जी के दिल में बसा है के सम्पूर्ण पर्यटन विकास खासतौर पर ग्रामीण पर्यटन और यमुना घाटों का निर्माण, पौराणिक मंदिर सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दें। हमें विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उचित वित्तीय सहायता से उत्तराखण्ड की पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

दो जिला चिकित्सालय सौंपे मेडिकल कॉलेजों को

रूद्रपुर और पिथौरागढ मेडिकल कॉलेजों को दो जिला चिकित्सालय सौंपने के आदेश हुए जारी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार शासन के द्वारा राजकीय मेडीकल कॉलेज रूद्रपुर और पिथौरागढ के सुचारू संचालन के लिए जिला चिकित्सालय रूद्रपुर तथा पिथौरागढ के जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री सचिन कुर्वे द्वारा इस संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए पं. रामसुमेर शुक्ल, राजकीय मेडिकल कालेज, रूद्रपुर के संचालन हेतु जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर और राजकीय मेडिकल कालेज, पिथौरागढ के संचालन हेतु बी.डी. पाण्डेय जिला चिकित्सालय पिथौरागढ एवं महिला चिकित्सालय पिथौरागढ को चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश जारी किए हैं। यह सभी चिकित्सालय अभी तक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन थे। शासन के द्वारा जारी आदेशानुसार हस्तांतरण के बाद इन चिकित्सालयों का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य/निदेशक के अधीन होगा। उक्त चिकित्सालय में एम.सी.आई. के मानकानुसार अवशेष वांछित उपकरणों एवं औषधियों की व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी। इन चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ के वेतन का भुगतान एक वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा तथा एक वर्ष के उपरान्त इन चिकित्सा इकाईयों का विधिवत् संचालन पूर्णरूपेण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

बीएलओ आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन मे बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीलएओ, ईआरओ सहित पूरी इलेक्शन मशीनरी ने बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश के युवा एवं महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा। आउटरीच अभियान के दूसरे चरण को 15 फरवरी 2026 तक सम्पादित किया जाएगा।

'आसानी से सर्च कर सकते हैं 2003 की मतदाता सूची में नाम'

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्री एसआईआर फेज में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अभियान में अपने बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने तथा अपने पिता/पति के नाम के आधार पर मतदाता क्रमांक एवं बूथ संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गली, मोहल्लों और एरिया के नाम से भी मतदाता सूची खोजने की सुविधा प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से बीएल नियक्त करने की अपील

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के 12070 बीएलए की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने राजनैतिक दलों से शतप्रतिशत बीएलए नियुक्त करने की अपील की है।

अवैध खनन पर रोक, राजस्व पहुंचा 1200 करोड़ पार

अवैध खनन में लिप्त लोग हुए बैचेन

2024 में लागू हुई नई खनन नीति से पूर्व राजस्व था मात्र 300 करोड़

खनन गतिविधियों को लेकर सामान्य तौर लोगों में नकारात्मक अवधारणा रहती है। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन आवंटन और खनन परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही अवैध खनन पर सख्ती दिखाई, इसी का नतीजा है कि डेढ़ साल से कम समय में सालाना खनन राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। नई खनन नीति में ई निलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन, खनन गतिविधियों की सेटेलाइट निगरानी जैसे कई नए प्रयोग किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस- प्रशासन को भी अवैध खनन पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सिर्फ 300 करोड़ रुपए तक ही सालाना राजस्व प्राप्त हो पाता था, लेकिन अब यह राजस्व 1200 करोड़ के पार चला गया है। यही नहीं उत्तराखंड को खनन सुधार लागू करने के लिए देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)" के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए रूपये 200 करोड़ की विशेष सहायता स्वीकृत की है।

इन सुधारों से बदली तस्वीर

ई निलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई खनन परिवहन के लिए माइनिंग सर्विलांस सिस्टम खनन गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और निरीक्षण आम लोगों को आवासीय या अन्य निर्माण के लिए खनन सामग्री की आवश्यकता होती है, साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी खनन की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खनन पर्यावरण के मानकों के अनुसार हो, साथ ही इसके लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया गया। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इससे राजस्व में भी शानदार वृद्धि हुई है, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है।

आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में 'प्रगति पोर्टल' की अहम भूमिकाः मुख्यमंत्री

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार के प्रगति पोर्टल विषय पर पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार (पीआईबी) देहरादून द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के बारे में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। वार्ता के दौरान धामी ने जानकारी दी कि परियोजनाओं, योजनाओं एवं जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान के लिए पोर्टल- प्रो एक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभिन्न योजनाएं जो देश के अंदर संचालित होती हैं उनकी समीक्षा के लिए प्रगति पोर्टल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। प्रगति पोर्टल भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी करता है और पोर्टल में आई समस्याओं का समाधान भी करता है। जिसकी वजह से विकास की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरती हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि 2014 के बाद से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, हवाई सेवा की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में 3.50 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, इनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये के 15 हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स का रिव्यू PRAGATI मैकेनिज्म के तहत किया जा रहा है। इनमें से

- भारत सरकार के प्रगति पोर्टल विषय पर पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित
- परियोजनाओं, योजनाओं एवं जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान के लिए 2015 में बनाया गया (प्रगति) पोर्टल
- मौजूदा समय में उत्तराखंड में 3.50 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, इनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये के 15 हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा प्रगति मैकेनिज्म के तहत की जा रही है: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- 10 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई, 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा- श्री धामी
- पर्यटन, चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूण ी होगी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- भारत सरकार से इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत निवेश हेतु उत्तराखंड को विशेष सहायता योजना के मद में 1800 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

अब तक 10 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जो 32 परियोजनाएं अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं उनमें से 12 परियोजनाएं PRAGATI पोर्टल के तहत मॉनिटर की जा रही हैं। इनमें सड़क और राजमार्ग की 19 परियोजनाएं, ITèkITES की 3 परियोजनाएं, ऊर्जा उत्पादन की 3 परियोजनाएं, रेलवे की 2 परियोजनाएं, कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत, अपशिष्ट और जल प्रबंधन में एक-एक परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़ी परियोजनाएं जैसे चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हुआ है। इसी प्रकार ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन देश की प्रमुख परियोजना है जो पहाड़ों के बीच से हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंच रही है। इस परियोजना का काफी काम पूरा हो चुका है और परियोजना के पूरा होते ही यह क्षेत्र पर्यटन, चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। साथ ही सामरिक रूप से भी इसका महत्व बढ़ेगा, क्योंकि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन पहुंचने से मानसून वर्षाकाल में जो रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। इस रेलवे लाइन के बिछने से लोगों का सफर आसान हो जाएगा। सीएम धामी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी, देहरादून आने वाले सभी देश-दुनिया के पर्यटक लाभान्वित होंगे। जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन सभी पर तेजी से काम चल रहा है। जिनकी समीक्षा प्रतिदिन भारत सरकार के प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है जिसमें प्रगति पोर्टल का अहम रोल है। भागीरथी इको संसेटिव जोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस चुनौतिपूर्ण परेशानी को दूर करने के प्रयास करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26' के तहत उत्तराखंड के लिए रूपये 734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस दोहरी सौगात के साथ चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा उत्तराखंड को SASCI योजना के अंतर्गत दी गई कुल सहायता अब रूपये 1,806.49 करोड़ के प्रभावशाली आंकड़े तक पहुँच गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने और 'विकसित उत्तराखंड' के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।

स्मार्ट बनेगा सचिवालय भवन

मुख्यमंत्री धामी के विजन को जमीन पर उतारने में जुटा आवास विभाग

• सचिवालय में आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण को मिली रफ्तार, औचक निरीक्षण में आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश

आवास विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार विभागीय कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को जमीन पर उतारने और सरकारी कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से डॉ. राजेश कुमार ने आज सचिवालय परिसर स्थित निर्माणाधीन आधुनिक कार्यालय भवन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ एसएस रावत संयुक्त सचिव, राज्य संपत्ति, नीरज कुमार त्रिपाठी, अधिशाषी अभियंता लोकनिर्माण विभाग, संदीप वर्मा, अपर सहायक अभियंता सिविल, गाविंद सिंह, सहायक अभियंता विधुत सहित ठेकेदार शिव कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। राज्य सम्पत्ति विभाग एवं निर्माण से जुड़े संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा। राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय परिसर, देहरादून में विश्वकर्मा भवन के समीप 6 मंजिला (जी5 एवं एक बेसमेंट सहित) आधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भवन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए आधुनिक, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक कार्यालय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस परियोजना को शासनादेश दिनांक 26 मार्च 2025 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन निर्माण की कुल लागत रूपये 5934.71 लाख है, जिसमें सिविल कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। अब तक इस परियोजना पर लगभग रूपये 1400 लाख की धनराशि का आंवटन किया जा चुका है।

निर्माण एजेंसी और समय-सीमा

भवन के सिविल निर्माण कार्य का अनुबंध मैसर्स शिव कुमार अग्रवाल को दिया गया है। निर्माण कार्य को डेढ़ वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना है, जिसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

भवन की प्रमुख विशेषताएं

यह भवन 34×74 मीटर के प्लॉट पर निर्मित किया जा रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2516 वर्ग मीटर है। सभी मंजिलों को मिलाकर भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1,04,480 वर्ग फीट होगा। भवन के बेसमेंट में 25 कार पार्किंग और 100 दोपहिया वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सचिवालय परिसर में पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर एसबीआई बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रवेश लॉबी और वेटिंग एरिया का प्रावधान किया गया है। ऊपरी मंजिलों पर सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अनुसचिव, स्तर के कार्यालय व उनके स्टाफ कक्ष, वेटिंग लॉबी और मीटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं।

निर्माण की वर्तमान स्थिति

निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार भवन का फाउंडेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। बेसमेंट का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है तथा ग्राउंड फ्लोर का कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 15 प्रतिशत है। राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह भवन सचिवालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाएगा।

गुणवत्ता से समझौता नहीं- डॉ आर राजेश कुमार

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा सचिवालय परिसर में निर्माणाधीन यह आधुनिक कार्यालय भवन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप हम सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार आगे बढ़े। यह भवन भविष्य में बेहतर कार्यसंस्कृति और सुगम प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यूजेवीएन लिमिटेड में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिक और खिलाड़ी हुए सम्मानित

यूजेवीएन लिमिटेड के मुख्यालय एवं अन्य कार्यस्थलों पर 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्यालय उज्ज्वल में आयोजित कार्यक्रम में निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अपने संबोधन में डॉ. संदीप सिंघल ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि संविधान, समानता, स्वाभिमान और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान निर्माताओं के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरव के साथ खड़ा है। डॉ. सिंघल ने अपने संबोधन में यूजेवीएन लिमिटेड की वर्तमान गतिविधियों एवं निगम की भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि निगम का लक्ष्य है कि नवीन तकनीकों, कुशल मानव संसाधन एवं बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से वर्ष 2032 तक विद्युत उत्पादन को दोगुना तथा टर्नओवर को तीन गुना करने के लक्ष्य की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस लक्ष्य में जलविद्युत के साथ-साथ अन्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना भी शामिल है। समारोह के दौरान विनोद गुसांई, विवेक आत्रेय, नीरज तिवारी, महकार सिंह, रेखा डंगवाल, आदित्य राठी, रत्नेश बिष्ट एवं ज्योति कोहली द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीत एवं व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात प्रबंध निदेशक, निदेशक एवं अधिशासी निदेशकों द्वारा खेलकूद एवं निगम के दैनिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ललित टम्टा, गोपाल सिंह, सुमित राणा, प्रशांत कुमार, आशीष सिंह बिष्ट, आदित्य राठी तथा रक्षित भंडारी को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मानित होने वालों में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा गार्ड श्रेणी में अशोक पांडे विजेता घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ उपनल कर्मचारी कंप्यूटर आपरेटर पुरुष वर्ग में संदीप कुमार एवं सुनील सिंह नेगी संयुक्त विजेता तथा महिला वर्ग में श्रीमती ललिता नौटियाल को विजेता घोषित किया गया जबकि उपनल चतुर्थ श्रेणी वर्ग में जफर बेग उपविजेता रहे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पुरुष वर्ग में नामदेव शर्मा विजेता तथा महिला वर्ग में श्रीमती सरस्वती देवी विजेता रहीं। इसी श्रेणी में पुरुष वर्ग में वीरेंद्र कुमार को उप-विजेता घोषित किया गया।तकनीकी कर्मचारी श्रेणी में पुरुष वर्ग में विजेता राम निवास तथा उप-विजेता वीरेंद्र कुमार तथा गोविंद प्रसाद रहे, जबकि महिला वर्ग में सुश्री सीमा को विजेता घोषित किया गया। इसी प्रकार मिनिस्ट्रियल कर्मचारी श्रेणी में पुरुष वर्ग में हेम चंद्र लोहानी विजेता तथा सुदीप चंद्र उनियाल उप-विजेता रहे, जबकि महिला वर्ग में श्रीमती नेहा जैन विजेता घोषित की गई। इसके अतिरिक्त गैर-तकनीकी अधिकारी पुरुष श्रेणी में नरेंद्र सिंह एवं महिला श्रेणी में श्रीमती शालिनी उनेरिया को विजेता घोषित किया गया। अवर अभियंता पुरुष श्रेणी में ललिता प्रसाद बुडाकोटी विजेता एवं रिनिश कुमार उपविजेता तथा महिला वर्ग में सुश्री शिवानी विजेता घोषित हुई। अभियंता पुरुष श्रेणी में यशपाल महर एवं अतुकांत शर्मा संयुक्त विजेता तथा कृष्ण कुमार गुप्ता एवं अभिनव सिंह संयुक्त उप-विजेता रहे। महिला अभियंता श्रेणी में श्रीमती बबीता कोहली विजेता रही। कार्यक्रम का संचालन अधिशासी अभियंता राकेश कुमार चौहान द्वारा किया गया।

हिमालय से निकलने वाली नदियों, जलधारों, ग्लेशियर आदि को मानव जीवन के साथ-साथ जैव विविधता के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक: डॉ. पंत

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा संचालित 'जल शिक्षा कार्यक्रम' के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 को *उत्तराखंड के जल संसाधन: वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां एवं सतत समाधान (वाटर रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड: 'प्रेजेंट स्टेटस, इमर्जिंग चैलेंजेज एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस)* विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने अपने संबोधन में कहा कि यूकॉस्ट द्वारा जल स्रोतों के महत्व को देखते हुए आम जनमानस एवं विद्यार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से वाटर एजुकेशन कार्यक्रम प्रादेशिक स्तर पर चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है कि प्रदेश के जल संसाधनों का संरक्षण एवं उनके वैज्ञानिक अध्ययन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों, जलधारों, ग्लेशियर आदि को मानव जीवन के साथ-साथ जैव विविधता के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक बताया। प्रो. पंत ने कहा कि भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने के लिए जल स्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यूकॉस्ट द्वारा ''मां धरा नमन'' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 100 विभिन्न जल स्रोतों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर यूकॉस्ट के संयुक्त निदेशक डॉ. डी.पी. उनियाल ने यूकॉस्ट द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों व परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक यूकॉस्ट वैज्ञानिक डॉ भवतोष शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

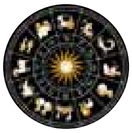
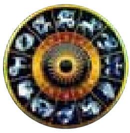

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- अपने रिश्तों के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना और अधिक नजदीकियां बढ़ाएगा। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी। अत्यधिक क्रोध और जल्दबाजी आपके बनते कार्य बिगाड़ सकती है, इसलिए अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 5

वृषभ राशि- पारिवारिक तथा आर्थिक गतिविधियों को सुलझाने में ही व्यस्तता बनी रहेगी। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवा पढ़ाई पर ध्यान दें। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। प्रेम संबंधों में नकारात्मक बात की वजह से दूरियां आ सकती हैं। थोड़ी बहुत खांसी-जुकाम जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 3

मिथुन राशि- किसी भी कार्य को सहज तरीके से करने का प्रयास करें, आपको लाभदायक नतीजे मिलेंगे। संतान पक्ष की किसी गतिविधि से मन में प्रसन्नता रहेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में विशेष जानकारी न दें, अन्यथा कोई आपको धोखा दे सकता है। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें, राहत मिलेगी। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

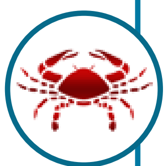

कर्क राशि- विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वरना भविष्य में पछताना पड़ सकता है। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को तय समय पर पूरा कर लें। इस समय फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं। घर में मनोरंजक गतिविधियों में एक-दूसरे के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

सिंह राशि- इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। अचानक ही आपको कहीं से सहयोग और उचित सलाह भी हासिल होगी। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। आपकी योजनाएं और कार्य क्षमता बिजनेस को नई गति प्रदान करेगी। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 4

कन्या राशि- राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी। कुछ समय एकांत अथवा धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी और कार्यभार भी बना रहेगा। गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन लें। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 1

तुला राशि- आज दिनचर्या व्यवस्थित करने में कुछ मेहनत रहेगी, लेकिन आप उसके उचित परिणाम जरूर हासिल कर लेंगे। संपर्कों तथा सामाजिक सक्रियता का दायरा बढ़ाने से खास जानकारियां भी मिलेंगी। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय न लें। संतान की पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या अभी बनी रह सकती है। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 8

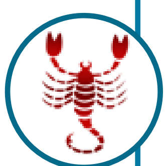

वृश्चिक राशि- आप अपने आत्मविश्वास और सूझबूझ द्वारा किसी भी विपरीत परिस्थिति में समाधान निकाल लेंगे। भावनात्मक रूप से मजबूत रहें और किसी की बातों में न आएं। अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाएं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अपने कार्यों में जीवनसाथी की सलाह लेना भाग्योदय कारक रहेगा। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 9

धनु राशि- आपके उत्तम व्यवहार की वजह से लोगों के सामने अच्छी इमेज बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अपने करियर से संबंधित उचित उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं। प्रशंसा मिलने पर अपने अंदर अहम की भावना न आने दें। इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से संबंधित व्यवसाय ज्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

मकर राशि- आज अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी कार्य की प्लानिंग करें। अधूरे पड़े हुए कार्यों में भी सुधार आएगा। साथ ही किसी असंभव कार्य के अचानक बन जाने से मन में प्रसन्नता रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन बना रहेगा। युवा वर्ग भरपूर आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखेंगे। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 2

कुंभ राशि- खास और प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिले, तो उसे हाथ से न जाने दें। उनके मार्गदर्शन में आपको कई बेहतरीन सुझाव मिलेंगे। फाइनेंस संबंधी कार्यों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 8

मीन राशि- किसी अनुभवी अथवा गुरु तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप अपने काम को प्रगति पर लेकर जा सकते हैं। अपने हुनर अथवा काबिलियत को सबके समक्ष लाने का उचित समय है। स्त्री वर्ग अपने किसी खास कार्य को संपन्न करने में विशेष प्रयास करेंगी और सफल भी रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 7

उत्तराखण्ड शासन

संकल्प से शिखर तक

गणतंत्र दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएँ

26 जनवरी

❝ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक कहा है। हम प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिये विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। ❞

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

❝ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है। ❞

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

संकल्प नये उत्तराखण्ड का

- स्वतंत्र भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश में प्रथम राज्य बना उत्तराखण्ड।
- नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI) 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किया प्राप्त।
- बीते 4 वर्षों में 26,500 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मिली मंजूरी। प्रदेश में संचालित मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से लेनी होगी मान्यता।
- राज्य में 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि हुई अतिक्रमण से मुक्त।
- राज्य के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट।
- ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ₹ 3.56 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हुए साईन। इस वर्ष तक ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की हो चुकी ग्राउंडिंग।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी States' Startup Ecosystem Ranking (5वां संस्करण) में उत्तराखण्ड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में 'लीडर' के रूप में मिली मान्यता।
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हुआ लागू।
- राज्य में सशक्त भू कानून हुआ लागू।
- राज्य में सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, एवं दंगारोधी कानून हुआ लागू।
- राज्य में कुल 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड किए गए वितरित।
- उधम सिंह नगर के किच्छा में एम्स की सैटलाइट सेंटर का निर्माण कार्य गतिमान।
- राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हुआ लागू। सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित।
- शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को ₹ 10 लाख से बढ़ाकर किया ₹50 लाख। परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि ₹50 लाख से बढ़ाकर की गई डेढ़ करोड़।
- केदारनाथ पुनर्निर्माण और बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कार्य गतिमान। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पौराणिक मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जारी।
- गौरीकुण्ड से केदारनाथ एवं गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास।
- दिल्ली देहरादून के बीच एलिवेटेड रोड के बनने से 2.5 घंटे में सफर होगा पूरा।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य तेज गति से गतिमान। अब तक 70 प्रतिशत कार्य हुआ पूरा।
- नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडेक्स में उत्तराखंड को मिला देश में प्रथम स्थान।
- छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि की हुई शुरुवात।
- खनन सुधारों में उत्तराखण्ड का उत्कृष्ट प्रदर्शन, देश में हासिल किया दूसरा स्थान, केंद्र सरकार से जारी की ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि।
- उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया सफल आयोजन, कुल 103 पदक जीतकर, पदक तालिका में 7वां स्थान किया हासिल।
- राज्य के स्कूलों में बच्चों के पाठ्यचर्या में शामिल होगा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 मंजूरी

विकास के नये अध्याय
की ओर अग्रसर

देवभूमि
उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह

स्थानीय लोगों से:
बोली भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिबारी वाले घरों को संवारें

पर्यटकों से:
सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।

www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

@DIPR_UK #ExploreUttarakhand

SOCIETY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN SCIENCE,TECHNOLOGY AND AGRICULTURE

SCIENCE POPULARIZATION | RESEARCH | INNOVATION | EDUCATION | TRAINING

HAPPY

Republic Day

May our nation continue to grow in peace, prosperity, unity, and the light of science and innovation.

77th REPUBLIC DAY

26 JANUARY 2026

DEHRADUN INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY FESTIVAL

www.dehradunsciencefest.org

Head Office:
6, Municipal Road, Opposite Oxford School,
Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand
Mobile: +91 8433456398, 9410353164
Email: sradstauk@gmail.com

विज्ञान संप्रेषण

vigyansampreshan@gmail.com
subscription.vigyan@gmail.com

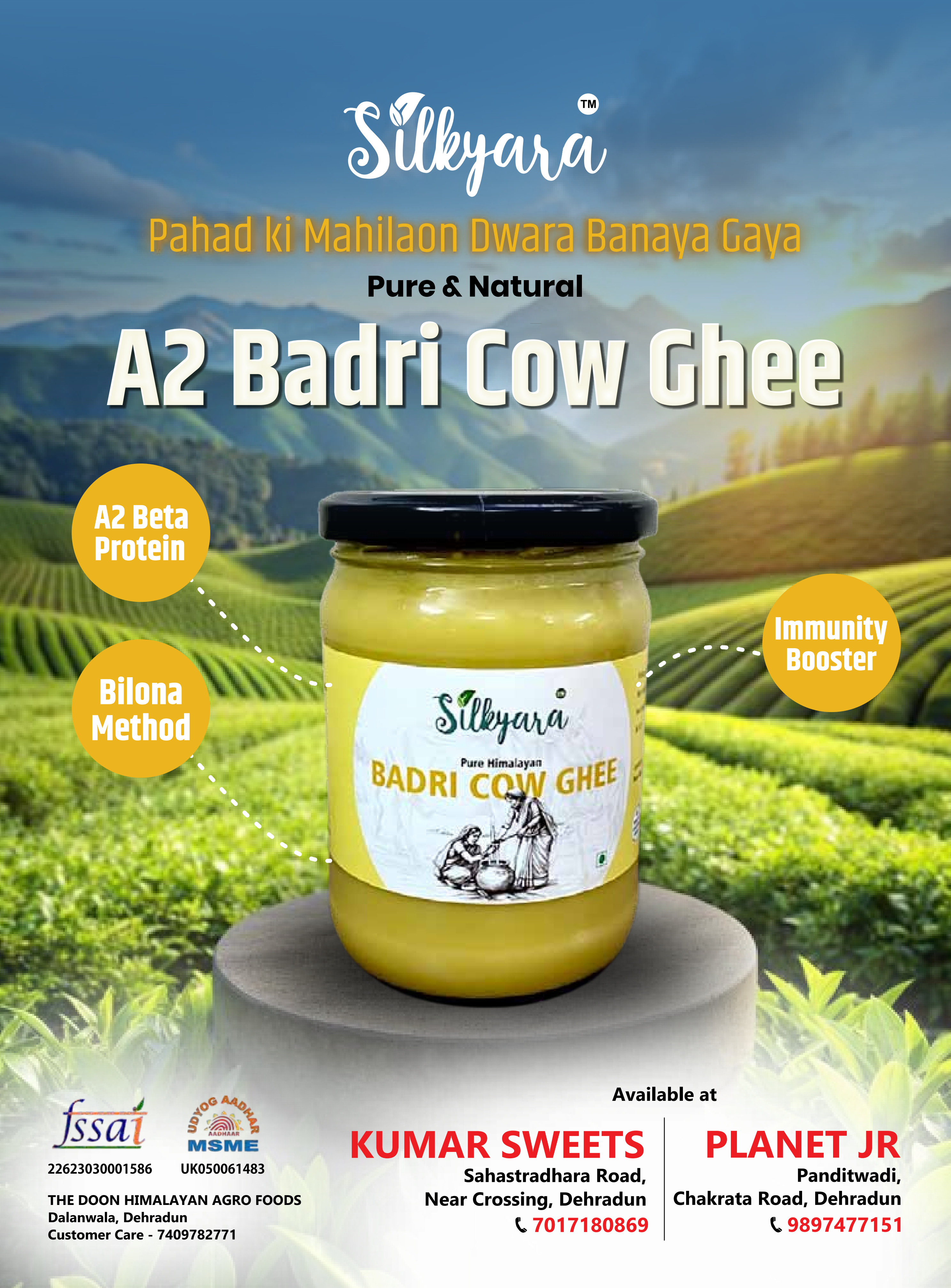
Silkyara™
Pahad ki Mahilaon Dwara Banaya Gaya
Pure & Natural
A2 Badri Cow Ghee
A2 Beta Protein
Bilona Method
Immunity Booster
Silkyara
Pure Himalayan
BADRI COW GHEE
fssai
22623030001586
UDYOG AADHAR
MSME
UK050061483
THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dalanwala, Dehradun
Customer Care - 7409782771
Available at
KUMAR SWEETS
Sahastradhara Road,
Near Crossing, Dehradun
7017180869
PLANET JR
Panditwadi,
Chakrata Road, Dehradun
9897477151

Rishikesh HANDMADE
soulful handmade creations

PREMIUM AUTHENTIC PRODUCTS OF

HIMALYAN FIBRE

Rishikesh
Natural Fiber Handicrafts Producer Company Pvt. Ltd.

Visit for Products: ***www.rishikeshhandmade.com***

MOTHER CONCERN

BHARTIYA GRAMOTTHAN SANSTHA

Gramotthan Bhawan:
Upper Road Dhalwala (Rishikesh)
Tehri Garhwal, Uttrakhand 249201
Email: *bgsuttranchal@rediffmail.com*
Contact: *(+91) 7351009107, 9411571947*
Website: *https://bgsuttarakhand.org.in/*

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027